

पाँच रुपये  
FIVE RUPEES

दस रुपये  
TEN RUPEES

(8)

15/-

CF 115 ✓

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वा लियर  
पुकारण सुंमाक । २००६ निगरानी

R 2301-III/06

श्री लोकेश की नामिक ११२०६/८३  
द्वारा आज दि. ११२०६/६ को प्रस्तुत ।  
बवर सचिव  
राजस्व मण्डल म० प० ग्वा लियर

किशोरसिंह पुत्र हरगौविन्द जाति कमरिपा  
आमु-पूर्ण वर्डी, व्यवसाय-कृषि  
निवासी-ग्राम जैन्हार तहसील व जिला  
दतिया म०पु०

-- आवैदक

बनाम

- १- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कौटर वास्ते अपर  
कौटर, दतिया  
२- अनुविभागीय शशिकला अधिकारी जिला दतिया  
(म०पु०)

-- अनावैदकगण

निगरानी अन्तर्गत द्वारा ५० मध्यप्रदेश मूँराजस्व सुंहिता  
१६५६ विलद आदैश दिनांक २६-११-२००६ श्रीमान अपर  
आमुका ग्वा लियर सुंमान ग्वा लियर जै पुकारण सुंमाक  
४८१ १०५-०६ अप्रील मूँ पारित किया गया।

माननीय न्यायालय,

आवैदक - मुनरीकाण कर्ता की ओर से

मुनरीकाण निम्नप्रार प्रस्तुत है-

मुनरीकाण के सुनिकाप्त तथ्य-

- १- यहकि प्राथी आवैदक के पक्ष मूँ अनुविभागीय अधिकारी  
दतिया द्वारा पुकारण सुंमाक शक्ति १७०८ वी । १२१ ।  
२००१-०२ के अन्तर्गत पाथीकि साति की मूमि मूँ स्थित  
शासकीय कुआँ का व्यवस्थापन प्राथीकि हित मूँ किया  
गया था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 230+दो/2006 निगरानी

जिला दतिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	<p>उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 481/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2006 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ अनुविभागीय अधिकारी, दतिया के प्रकरण क्रमांक 1708-बी-121/2001-02 में ग्राम जोन्हार स्थित कूप व्यवस्थापन के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 3-3-06 पर से प्रकरण प्रारंभ है एंव इस आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-8-06 से अपील अस्वीकार हुई, जिसके विरुद्ध अपर अयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई है। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 481/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2006 निगरानी अस्वीकार की गई है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जबकि संहिता की किसी भी धारा में कूप व्यवस्थापन का विषय समाहित नहीं है जिसके कारण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।</p> <p>3/ शासकीय कूप (कुआ) व्यवस्थापन मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप</p>	

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 963/16-110/77/सात/2 दिनांक 4 जून, 1970 में कूप व्यवस्थापन पर अपील/निगरानी की निम्नानुसार व्यवस्था है :-

- प्रदेश में शासकीय कुओं का व्यवस्थापन पूर्ववत् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता रहेगा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध केवल एक अपील जिलाध्यक्ष को हाँगी। अपील में जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर या स्वप्रेरणा में पुनरावलोकन सुनने का अधिकार आयुक्त को होगा।

स्पष्ट है कि आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम है जिसके विरुद्ध अपील निगरानी की आगे व्यवस्था उक्त ज्ञापन में नहीं दी गई है जिसके कारण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है।



सदस्य